RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 318
दि. 22.03.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मथुरा में फरसे वाले बाबा की मौत पर हंगामा, सीएम योगी बोले- अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे

लखनऊः (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोरक्षक फरसे वाले बाबा की मौत के बाद शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि गोतस्करों ने उन्हें कंटेनर से कुचल दिया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने सड़क उतर कर दिल्ली-आगरा हाईवे को जामकर जमकर बवाल काटा है। इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराधी किसी हाल में बख्शे न जाएं।

सीएम योगी ने फरसे वाले बाबा के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

चीजों को नफरत में बदलना बीजेपी से सीखिएः अखिलेश

वहीं, इस घटना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें इस बारे में सोचना होगा कि इखढ कहां तनाव पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं बची है। अगर किसी को यह सीखना है कि चीजों को नफरत में कैसे बदला जाता है, तो वे इखढ से सीख सकते हैं।

अगर मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर एक साधु के साथ ऐसा बर्ताव होता है, और काशी में जहां से प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, वहां एक छात्र सरेआम दूसरे छात्र की हत्या कर देता है तो पूरे प्रदेश में कोई भी, जो चाहे कर सकता है।

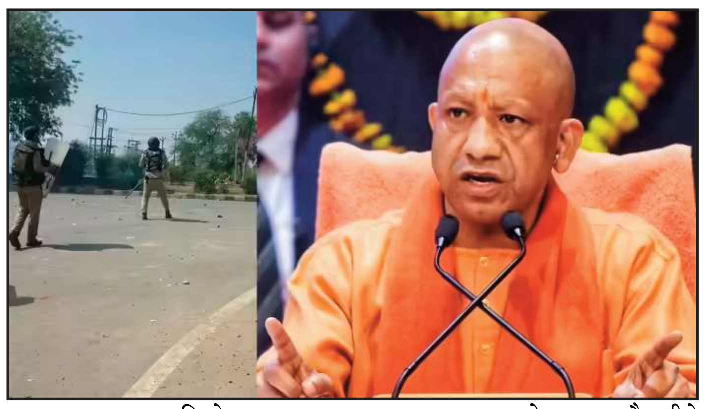

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

मथुरा में हालात नियंत्रण में: डीआईजी शैलेश पांडे

इस घटना को लेकर आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश पांडे ने बताया कि तड़के सुबह बरसाना थाना क्षेत्र के रहने वाले बाबा ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर मवेशियों की तस्करी के शक में एक ट्रक को रोक लिया था। उस समय घना कोहरा था और पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने रुके हुए ट्रक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में फरसे वाले बाबा घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत के बाद उनके कुछ समर्थकों और अन्य लोगों ने उनके शव को लेकर हाईवे जाम कर दिया है। रढ ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है।

फरसे वाले बाबा की मौत के बाद भड़के विरोध-प्रदर्शन पर वीएचपी नेता बच्चू सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की थी। फिर अधिकारियों ने उन्हें स्थिति समझाई और उन्हें वहां से हटा दिया है।

असम, केरल और पुडुचेरी में ईवीएम-वीवीपीएटी का पहला याद्दच्छिकीकरण कार्य पूरा

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और छह राज्यों में उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। ईवीएम का आवंटन दो चरणों वाली याद्दच्छिक प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित मतदान केंद्रों को किया जाता है। पहले चरण में, जिला स्तरीय गोदामों से विधानसभा क्षेत्रों को ईवीएम का याद्दच्छिक आवंटन किया जाता है। दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र स्तर से मतदान केंद्र स्तर तक ईवीएम का याद्दच्छिक आवंटन किया जाता है। ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, सभी मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीईओ को एफएलसी में मानकों को पूरा करने वाली ईवीएम-वीवीपीएटी मशीनों का पहला याद्दच्छिकीकरण पूरा करना होगा।

वन्यजीव संरक्षण पर प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 90वीं बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने सड़क, पेयजल आपूर्ति, पारेषण लाइनें, रक्षा, सिंचाई और अन्य अवसंरचनाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान, वन अग्नि प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और निर्णय समर्थन प्रणालियों में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, रिमोट सेंसिंग और एआई/एमएल-आधारित उपकरणों के उपयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) और भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

समिति ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की

और प्रजातियों के संरक्षण, आवास प्रबंधन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय पहलों की स्थिति पर ध्यान दिया।

समिति ने चंबल नदी में पर्यावरणीय प्रवाह के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया ताकि डॉलफि न, घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों जैसी नदी प्रजातियों को, विशेष रूप से कम जल स्तर के दौरान, संरक्षित किया जा सके।

समिति ने घास के मैदानों और चारागाहों के संरक्षण पर भी चर्चा की, जिसमें जैव विविधता, कार्बन पृथक्करण, शुष्क भूमि की सहनशीलता और पशुपालकों की आजीविका के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया। यह पाया गया कि नियोजन ढाँचों में इन पारिस्थितिक तंत्रों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है और इन्हें ईको सिस्टम विशिष्ट पुनर्स्थापन दृष्टिकोण, बेहतर मानचित्रण और भूमि क्षरण तटस्थता जैसी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ एकीकरण की आवश्यकता है। संरक्षित क्षेत्रों पर खानाबदोश और पशुपालक समुदायों की निर्भरता संबंधी विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

माई भारत राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पदयात्रा 2026 का आयोजन करेगा 'मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी' थीम के तहत 763 जिलों में

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे और हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम 23 मार्च 2026 को फरीदाबाद में युवाओं की अगुवाई वाली राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे

(जीएनएस)।

भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानियों - शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम राजगुरु और शहीद सुखदेव थापर - के अद्वितीय बलिदान को पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत (माई भारत) के माध्यम से शहीद दिवस के उपलक्ष्य में 23 मार्च, 2026 को एक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आयोजन करेगा। यह पहल 'मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी' थीम के तहत संचालित की जाएगी।

हर वर्ष, शहीद दिवस इस बात की सशक्त स्मृति प्रदान करता है कि भारत की आजादी बलिदान और साहस के बल पर अर्जित की गई थी। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि आजादी महज विरासत में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर सामूहिक प्रयासों से इसे मजबूत और संरक्षित भी किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में, शहीद दिवस पदयात्रा युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके स्मरण को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करती है।

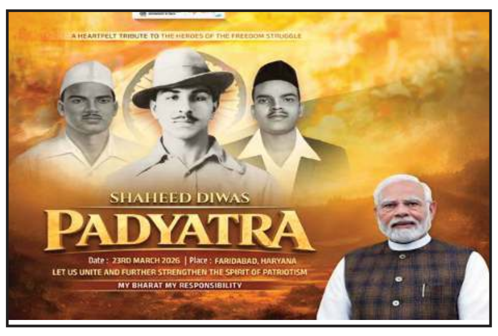

दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक के रूप में भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को देखते हुए, इस पहल का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, आदर्शवाद और आकांक्षाओं को जिम्मेदार नागरिकता की ओर निर्देशित करना है। 'मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी' की थीम अतीत के बलिदानों का सम्मान करने से लेकर भविष्य के कर्तव्यों को स्वीकार करने तक के बदलाव को दशार्ती है।

देश के सभी 763 जिलों में पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें से एक प्रमुख आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में होगा, जिसमें 10,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। एक एकीकृत राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में युवाओं के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी।

फरीदाबाद में होने वाली पदयात्रा राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का मुख्य आयोजन होगी और इसमें केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे और हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे, जिनकी उपस्थिति से युवाओं की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होगी।

फरीदाबाद में, यह पदयात्रा के.एल. मेहता दयानंद कॉलेज (प्रारंभिक बिंदु) से शुरू होगी और घंटा घर, मार्केट नंबर 5 (केसी रोड) सहित प्रमुख स्थलों से होते हुए लगभग 2.31 किलोमीटर की दूरी तय करके शहीद भगत सिंह चौक (एनएच-5) पर समाप्त होगी।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना से प्रेरित होकर, माई भारत युवाओं में नागरिक चेतना को बढ़ावा देने हेतु लगातार ऐसे आयोजन करता रहता है। अब तक 13 राष्ट्रीय स्तर की विकसित भारत पदयात्राएं, 108 राज्य स्तर की पदयात्राएं और 1,573 जिला स्तर की पदयात्राएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 21 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया है।

उपराष्ट्रपति ने मुंबई के लोक भवन में आयोजित ऐतिहासिक जैन दीक्षा समारोह के आयोजकों और दानदाताओं को सम्मानित किया

उपराष्ट्रपति ने मुंबई के लोक भवन में आयोजित ऐतिहासिक जैन दीक्षा समारोह के आयोजकों और दानदाताओं को सम्मानित किया

उपाध्यक्ष ने कहा कि त्याग और सेवा की भावना समाज के लिए प्रेरणा है

(जीएनएस)।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज हाल ही में मुंबई में आयोजित ऐतिहासिक जैन दीक्षा समारोह के आयोजकों, दानदाताओं और इससे जुड़े परिवारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दीक्षा समारोह में प्रतिबिंबित त्याग और सेवा भाव पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है।

लोक भवन में सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन धर्म हमेशा से ही समाज सेवा और अहिंसा, अपरिग्रह और सहिष्णुता के मूल्यों का प्रतीक रहा है, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जहां अधिकांश लोग सांसारिक जिम्मेदारियों में लिप्त रहते हैं, वहीं दीक्षा लेने वालों द्वारा किया गया त्याग समाज को चिंतन करने, जीवन को सरल बनाने और सचेत

जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत जैन धर्म सहित कई धर्मों की जन्मभूमि है। यूटी तमिलनाडु और जैन धर्म के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति ने संगम और उत्तर-संगम काल के दौरान तमिल साहित्य और संस्कृति में जैन विद्वानों और भिक्षुओं के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया और सिलप्पथिकारम जैसी शास्त्रीय रचनाओं और जैन धर्म के दार्शनिक और नैतिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाली अन्य साहित्यिक कृतियों का उल्लेख किया।

जैन दर्शन की सार्वभौमिक प्रासंगिकता पर जोर देते हुए, उपाध्यक्ष ने कहा कि अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सिद्धांत संघर्ष, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक विभाजन सहित कई समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि सादा जीवन जीना, सोच-समझकर उपभोग करना और करुणा का अभ्यास करना न केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि एक सतत और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी है।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

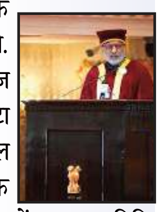

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज मुंबई स्थित रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और स्नातक छात्रों को कौशल विकास, रोजगार-योग्यता तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में संबोधित किया।

सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह दीक्षांत समारोह न केवल शैक्षणिक उपलब्धि का उत्सव है, बल्कि कुशल मानव पूंजी का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है।

श्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 45 वीं बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 45 वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान चिड़ियाघरों के प्रभावी प्रबंधन मूल्यांकन के दूसरे चरण के प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

' मेरा चिड़ियाघर ' की अवधारणा पर एक समिति का गठन किया जाए ताकि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को चिड़ियाघरों से जोड़ा जा सके।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आगामी बैठकों में चिड़ियाघरों द्वारा प्रति बैठक 2 से 3 प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन पर हुई प्रगति को प्रस्तुत किया जाएगा।

मानव-तेंदुआ नकारात्मक अंतःक्रियाओं में शामिल तेंदुओं को उन चिड़ियाघरों में स्थानांतरित करने के संबंध में अद्यतन जानकारी दी जानी चाहिए , जिन चिड़ियाघरों ने उनके दीर्घकालिक देखभाल के लिए दूर क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता की सूचना दी हो और जो उचित आवास, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करती हों।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर के आधुनिकीकरण की अवधारणा को अन्य चिड़ियाघरों के लाभ के लिए साझा किया जा सकता है।

चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों के लिए बंदी पशुओं के पोषण पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

आगामी बैठकों में नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अगली बैठक में चिड़ियाघर निदेशक द्वारा एक प्रस्तुति को शामिल किया जाए।

बैठक के दौरान 'कैद में देखभालः चिड़ियाघरों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाला संकलन' शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया। यह संकलन पशु कल्याण, संरक्षण प्रजनन, अनुसंधान और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन के प्रति भारत के विकसित होते दृष्टिकोण को उजागर करता है।

नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत 'तारागिरी' को कमीशन करने के लिए तैयार

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना, भारत की समुद्री संप्रभुता के एक निर्णायक समारोह में 3 अप्रैल 2026 को अपने नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत, तारागिरी (एफ41) को कमीशन करने की तैयारी कर रही है। विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले इस समारोह की अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह राष्ट्र के पूर्णतः आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का एक सशक्त प्रमाण होगा।

प्रोजेक्ट 17ए श्रेणी के चौथे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में तारागिरी केवल एक युद्धपोत नहीं है; यह 6,670 टन का 'मेक इन इंडिया' भावना और हमारे स्वदेशी शिपयार्डों की परिष्कृत इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रतीक है।

मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित यह युद्धपोत अपने पूर्ववर्ती डिजाइनों की तुलना में एक पीढ़ीगत विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आकार अधिक सुव्यवस्थित है और इसमें कम रडार क्रॉस-सेक्शन है, जिससे यह घातक स्टील्थ तकनीक से कार्य करने में सक्षम है।

राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सशक्त सेना और तैयार नागरिकों का होना आवश्यक हैः रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

आधुनिक समय का युद्ध सीमाओं से परे हैः रक्षा मंत्री

'युवाओं को आधुनिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए दूरदर्शिता, समझ, साहस और अनुकूलन क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है'

'सैनिक स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियां जल्द ही 'नारी शक्ति' की पथप्रदर्शक बनेंगी'

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'आजकल का युद्ध सीमाओं से परे है, राष्ट्रीय सुरक्षा में आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और यहां तक कि खाद्य सुरक्षा भी शामिल है।' उन्होंने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सक्षम, तैयार नागरिकों द्वारा समर्थित एक सशक्त सेना की आवश्यकता पर जोर दिया। 21 मार्च, 2026 को उत्तराखंड के घोराखाल स्थित सैनिक विद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और हीरक जयंती को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्षों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि आज किसी भी राष्ट्र को आर्थिक, साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध के माध्यम से कमजोर किया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को हर समय सतर्क और तैयार रहना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों को विशेष हथियारों और प्रौद्योगिकियों से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जबकि रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों, विशेषकर युवाओं को अनुशासन और दृढ़ संकल्प के माध्यम से मानसिक दृढ़ता और बौद्धिक स्पष्टता विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वे राष्ट्र को हर परिस्थिति से निपटने में मदद कर सकें। उन्होंने वूका (अस्थिरता, अनिश्चिता, जटिलता और अस्पष्टता) की अवधारणा का उल्लेख करते हुए छात्रों से आग्रह किया कि वे आधुनिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए वूका का अपना संस्करण विकसित करें , जिसमें दूरदर्शिता, समझ, साहस और अनुकूलन क्षमता शामिल है।

राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक मूल्यों को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य पहल में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में रिक्तियों की संख्या बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा, 'पहले एनसीसी में 17 लाख कैडेटों की भर्ती क्षमता थी; जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।'

रक्षा मंत्री ने सैनिक विद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश के निर्णय को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया, जिससे देश की 'नारी शक्ति' को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां आने वाले समय में 'नारी शक्ति' की पथप्रदर्शक बनेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुएंगी।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने नैनी में प्रदेश सचिव के घर पर ईद मिलन मे समलित हुये

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ/प्रयागराज

हम भाईचारा चाहते हैं। एकता का संदेश देना चाहते हैं। वर्तमान सरकार भाईचारा नहीं नफरत चाहती है। ऐसी नफरत वादी सरकार को हम हटाने का काम करेंगे महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सब से निजात पाने का सिर्फ एक रास्ता है, सामाजिक न्याय। देश और प्रदेश की जनता पीडीए के माध्यम से लामबद्ध हो रही है। यह बातें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने नैनी में प्रदेश सचिव के घर पर ईद मिलन के दौरान कहीं।

नैनी में शनिवार को प्रदेश सचिव मोहम्मद शारिक के आवास पर ईद मिलन का आयोजन का किया गया। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। जहां उनका सभी ने जोरदार स्वागत किया।

प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में संविधान की सरकार बनाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव करना ही नहीं चाहती। सरकार को अब तक पंचायत चुनाव करा देना चाहिए। सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाहती है।

जातीय जनगणना पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने प्रश्न उठाया था। ऊंच, नीच की जाति में एक मिडिल क्लास की जाति भी है, जो शिक्षा और समाज से काफी दूर है। अंग्रेज जनगणना करा कर सभी का हिस्सा देना चाहते हैं, वर्तमान सरकार ने संविधान के समय ही तय किया था कि सरकार बनती है तो, देश की पिछड़ी जाति की भी जनगणना होगी, लेकिन नहीहुआ।

उन्होंने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार को हटाकर पड़ा कि सरकार बनाना है। जिससे संविधान सुरक्षित रहे। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने नवरात्र और ईद के एक साथ पड़ने पर कहा कि यह प्रकृति का स्वरूप है, जो आपसी भाईचारे का पर्व ईद और नवरात्रि एक साथ देखने को मिल रहा है। हम सभी को इसे मिलजुल कर मानना चाहिए।

भाइयों पे जानलेवा हमला मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ/प्रयागराज

प्रयागराज। यमुनानगर जोन के करछना तहसील स्थित ग्राम पंचायत पिपरांव के भटौली गांव में दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में श्याम बाबू भारतीया (22) पुत्र स्वर्गीय रामधनी भारतीया के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि उनके बड़े भाई रामबाबू भारतीया (32) के हाथ में चोट लगी है।

पुलिस के अनुसार गांव के ही अनिल कुमार भारतीया तथा उसके भाई श्याम बिहारी भारतीया, पुत्र जगदीश, पेशे से सफाईकर्मी हैं। इन

दोनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।

किसी तरह अपनी जान बचाकर दोनों भाई घर पहुंचे, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित पक्ष ने करछना थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थाना प्रभारी करछना प्रवीण कुमार गौतम ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पीडीयूएनएएसएस ने डीओपीटी द्वारा प्रायोजित अनुभवात्मक शिक्षण उपकरणों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) ने नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में 16 से 20 मार्च, 2026 तक अनुभवात्मक शिक्षण उपकरण (ईएलटी) पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के तहत आयोजित किया गया था। यह सिविल सेवाओं में क्षमता विकास और प्रशिक्षण तंत्र को मजबूत करने पर सरकार के निरंतर प्रयास को दशार्ता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों में अनुभवात्मक अधिगम पद्धतियों का उपयोग करते हुए प्रभावी, शिक्षार्थी-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और प्रदान करने के लिए आवश्यक दक्षताओं का विकास करना था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सहभागिता बढ़ाने, व्यावहारिक अनुप्रयोग और वास्तविक दुनिया के संदर्भों के माध्यम से अधिगम परिणामों में सुधार करना था।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा सत्र संचालित किए गए जिनमें बीएसएफ के कमांडेंट श्री संदीप गुप्ता और व्याख्याता श्री लक्ष्मण मानिकपुरी शामिल थे। कार्यक्रम में केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, फील्ड आधारित शिक्षण और समूह अभ्यास जैसे कई अनुभवात्मक उपकरणों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में संवादात्मक और सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया।

इस प्रशिक्षण में व्यावहारिक अभ्यास, चिंतनशील अधिगम और सहयोगात्मक सहभागिता पर जोर दिया गया ताकि प्रतिभागी समकालीन शासन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावशाली प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर सके।

समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, पीडीयूएनएएसएस के निदेशक कुमार रोहित ने आधुनिक क्षमता विकास में अनुभवात्मक शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहाः

'अनुभवात्मक शिक्षण उपकरण प्रशिक्षकों को गहन और परिणामोन्मुखी शिक्षण वातावरण बनाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ज्ञान को सेवा वितरण में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पीडीयूएनएएसएस 'विकसित भारत' की परिकल्पना के अनुरूप एक सक्षम, उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण हेतु नवीन शिक्षण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।'

उन्होंने संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में डीओपीटी के प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।

इस कार्यक्रम में बीएसएफ, सीआईएसएफ, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान और ईपीएफओ सहित विभिन्न संगठनों के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रासंगिकता की सराहना की।

इस अवसर पर पीडीयूएनएएसएस के मुख्य शिक्षण अधिकारी श्री रिजवानुद्दीन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समन्वय पीडीयूएनएएसएस के प्रथम वरिष्ठ अधिकारी श्री विजय कुमार ने किया। उन्होंने पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में कार्य किया।

पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर प्रमुख क्षेत्रों के बारे में नवीनतम जानकारी

(जीएनएस)।

पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों की नवीनतम जानकारी नीचे दी गई है। इनमें ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए समर्थन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

ईंधन की आपूर्ति और उपलब्धता

होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैः

कच्चा तेल/तेल शोधन कारखाने

सभी तेल शोधन कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है।

शोधन कारखानों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में वृद्धि की गई है।

खुदरा दुकानें

तेल विपणन कंपनियों द्वारा किसी भी परिचालन केंद्र (आरओ) में ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार जनता को एक बार फिर सलाह देती है कि वे घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

प्राकृतिक गैस

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिसमें डी-पीएनजी और सीएनजी परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति शामिल है। ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत के बराबर है।

भारत सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।

आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल जैसी सीजीडी कंपनियों ने घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है।

पीएनजीआरबी ने सीडीजी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे आवेदन जमा करने और उपभोक्ता परिवारों को गैस आपूर्ति शुरू करने के बीच की समयावधि को कम करें।

भारत सरकार ने दिनांक 16.03.2026 के पत्र के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दिनांक 19.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी संबंधित केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि- सीजीडी अवसंरचना से संबंधित सभी लंबित और नई अनुमतियों के तत्काल त्वरित निपटान और निपटारे के लिए संबंधित विभाग/निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। भविष्य में सीजीडी से संबंधित अनुमति अनुरोधों को संसाधित करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध व्यवस्था भी स्थापित किया जा सकती है। सभी केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों/कॉलोनियों/अधिकारियों/कैंटीन ों को भी यह सलाह दी गई है कि वे जहां भी उपलब्ध हो, पीएनजी का उपयोग करना शुरू कर दें। भारत सरकार ने दिनांक 20.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में पीएनजी कनेक्शनों की संभावित मांग का व्यापक आकलन करें और इस अभ्यास के समन्वय के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करें।

፦ भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के जवाब में, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने अपने सभी कार्यालयों को सीजीडी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर अर्थात प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निपटान करने की सलाह दी है।

ट्ट प्रमुख शहरों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं से एलपीजी के स्थान पर पीएनजी (पेट्रोलियम-जनित गैस) का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

रसोई गैस, मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एलपीजी की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय है।

घरेलू एलपीजी आपूर्तिः, एलपीजी वितरकों में आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। अधिकांश आपूर्ति डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) के माध्यम से हो रही हैं। घबराहट में की गई बुकिंग में कमी आई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है। वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्तिः सरकार ने उपभोक्ताओं को आंशिक वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति (20 प्रतिशत) पहले ही बहाल कर दी है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से व्यापार सुगमता सुधारों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एलपीजी विस्तार के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत वाणिज्यिक एलपीजी आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत मुख्यमंत्री का आभार

(जीएनएस)।

लखनऊ। आपको बहुत-बहुत बधाई एवं प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने उ०प्र० उद्योग व्यापार संगठन की वर्षों पुरानी मांग को मानते हुए निर्णय लिया है, कि आगे 01अप्रैल 2026 से प्रदेश के खाद्य, फूड, किराना, रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई आदि सभी खुदरा व थोक व्यापारियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि अब फूड विभाग में मात्र ₹100 के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की सीमा 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है तथा 1 अप्रैल 2026 से पंजीकृत सभी लाइसेंस आजीवन कर दिए गए हैं यानी अब डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारी को मात्र ₹100 का पंजीकरण कराना होगा जो आजीवन के लिए मान्य होगा उसका रिनुवल कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश सरकार

के द्वारा व्यापार संगठन की इस मांग को माने जाने के बाद प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों को लाभ होगा साथियों यह सब आप की मेहनत व संगठन की व्यापारियों के प्रति राहत दिलाने की सोच से संभव हो पाया है इसलिए आप सभी बधाई के पात्र है। हम प्रदेश के व्यापारी अपने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से प्रदेश सरकार के इस निर्णय का का हृदय से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं साथियों आप भी यह जानकारी अपने-अपने जिले व नगर के सभी व्यापारियों को मीडिया के माध्यम से दें और अखबारों में विज्ञप्ति दे ताकि जिले व नगर के व्यापारियों को उ०प्र० उद्योग व्यापार संगठन की इस उपलब्धि की जानकारी हो तथा व्यापारी इसका लाभ उठा सकें।

पीलीभीत में मिशन शक्ति 5.0 की धूमः एसपी सुकीर्ति माधव ने हरी झंडी दिखाकर निकाली भव्य बाइक रैली, महिलाओं का सम्मान-देश का अभिमान!

(जीएनएस)।

पीलीभीत, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए चल रहे मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत जनपद पीलीभीत में शुक्रवार को महिला जागरूकता हेतु एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया।रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक श्री सुकीर्ति माधव ने पुलिस लाइन पीलीभीत से हरी झंडी दिखाकर किया। यह रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर नकटादाना चौराहा, गौहनिया चौराहा, छतरी चौराहा होते हुए असम चौराहे तक पहुंची। रैली में "महिलाओं का सम्मान-देश का अभिमान" जैसे नारों के जरिए समाज के हर वर्ग तक महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम दहिया, सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री नताशा गोयल, क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात, जनपद की सभी शाखाओं की महिला उपनिरीक्षक, महिला मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षी एवं पीआरवी कर्मियों ने प्रमुख रूप से भाग लिया।

यम दूत बनकर रोड पर दौड़ रही बाइक कार में मारी टक्कर।

(जीएनएस)।

हरदोई/कछौना थाना कासिमपुर गौसगंज में आम तौर पर एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती हैं वही आज तेज रफ़्तार बाइक सवार ने इनोवा कार में टक्कर मार दी। फिलहाल किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं हल्की फुल्की लगने की सूचना हैं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि थोड़ी बहुत बहस हुई फि लहाल मौके पर ही उपस्थित लोगों ने मामले को समझा बुझा का शांत कराया ज्यादा नुकसान न होने के कारण बाइक से

इनोवा कार में टक्कर साइड में लगना ही रहा मामले को आगे न बढ़ा कर दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग से सुलह समझौता कर एक दूसरे के नुकसान की भरपाई कर दी गयी है। वहां उपस्थित स्थानीय लोगों ने कई घटनाओं को लेकर बाइक सवार को रूबरू करवाया और बाइक तेज न चलाने की सलाह दी। यातायात व्यस्त रहने वाला मार्ग होने के कारण यहां अक्सर कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती रहतीं हैं जिसके चलते लोगों को तेज रफ़्तार वाहन न चलाने की सलाह रहती हैं। जिस समय यह घटना घटी फि लहाल उस टाइम दुकानें बंद हो चुकी थी और लोग अपने घर जा चुके होते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा कम होने के कारण कोई बड़ी घटना का रूप नहीं बनी।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) अकादमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण तथा मान्यता बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा उत्कृष्टता का नेतृत्व करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

कार्यनीतिक साझेदारी से एक औपचारिक ढांचा तैयार होगा जहां एसएसबी अकादमी में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरआरयू अकादमिक मान्यता प्रदान करेगा

इस सहयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा में अकादमिक अनुसंधान और सीमा सुरक्षा बलों की व्यावहारिक तथा जमीनी आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में स्थापित आरआरयू का प्राथमिक उद्देश्य एसएसबी से संचालित मौजूदा और भावी पाठ्यक्रमों को मान्यता देना है

आरआरयू पेशेवर विकास के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एसएसबी कर्मियों को अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और क्षेत्र-आधारित कार्यशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा

इस पहल से सीमा निगरानी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एसएसबी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीनतम होने की उम्मीद है

इस पहल का उद्देश्य दोनों संस्थानों की प्रतिभाओं का लाभ उठाकर एसएसबी के भीतर निरंतर पेशेवर विकास के लिए एक मजबूत परितंत्र तैयार करना है

(जीएनएस)। देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में उठाए गए कदम में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) अकादमी ने अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ विशेष सुरक्षा पाठ्यक्रमों को संबद्ध और मान्यता देने के लिए आज आधिकारिक तौर पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। औपचारिक हस्ताक्षर समारोह दिल्ली में एसएसबी मुख्यालय में हुआ, जिसमें आरआरयू के प्रो-वाइस चांसलर प्रोफेसर (डॉ.) कल्पेश एच. वांड्रा; आरआरयू में संबद्धता और प्रत्यायन के डीन श्री अविनाश खरेल; और एसएसबी के महानिदेशक (डीजी) श्री संजय सिंघल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

यह कार्यनीतिक साझेदारी एक औपचारिक ढांचा तैयार करती है जहां राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आरआरयू, एसएसबी अकादमी में आयोजित

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक मान्यता प्रदान करेगा। समझौते की शर्तों के तहत, दोनों संस्थानों ने संकाय विशेषज्ञता, शैक्षणिक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं सहित संसाधनों के व्यापक आदान-प्रदान के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस सहयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा में अकादमिक अनुसंधान और सीमा सुरक्षा बलों की व्यावहारिक तथा जमीनी आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है।

कार्यक्रम के दौरान, प्रोफेसर (डॉ.) कल्पेश एच. वांड्रा ने कहा कि यह सहयोग पहले से ही परिणाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि आरआरयू ने हाल ही में एसएसबी अधिकारियों के लिए एक विशेष "स्मार्ट सीमा प्रबंधन" पाठ्यक्रम आयोजित किया है। पेशेवर विकास के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, आरआरयू एसएसबी कर्मियों को अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और क्षेत्र-आधारित कार्यशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस पहल से एसएसबी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीनतम होने की उम्मीद है, जिसमें सीमा निगरानी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

एसएसबी महानिदेशक श्री संजय सिंघल ने बल के लिए आवश्यक शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आरआरयू की क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस साझेदारी में अधिकारियों को सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा के उभरते परिदृश्य के अनुकूल तैयार करने के लिए उनका "कौशल विकास और पुनः कौशल" पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दोनों संस्थानों की प्रतिभाओं का लाभ उठाकर सशस्त्र सीमा बल के भीतर निरंतर पेशेवर विकास के लिए एक मजबूत परितंत्र बनाना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में स्थापित इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिसिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करना है। इसके लिए यह विशेषज्ञों के एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक अनुशासित ढांचे के भीतर विशेष पेशेवर शिक्षा प्रदान करता है।

इस टङ्क्षव के तहत, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (फ्क्क्व) रस्ड्ढ द्वारा संचालित मौजूदा और भविष्य के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप, फ्क्क्व के 'पाठ्यक्रमों के संयुक्त प्रत्यायन और प्रमाणन दिशानिर्देशों' के आधार पर संबंधित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र (ऊी१ड्डद्बद्घ), डिप्लोमा, ढद्द डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, स्नातक (ड्ढ'ड्ड१'२) या स्नातकोत्तर (टं२ड्ढ१'२) की डिग्री प्रदान की जा सकती है।

इस साझेदारी में कार्यान्वयन के लिए एक तार्किक ढांचा शामिल हैः

पाठ्यक्रम मूल्यांकनः आरआरयू प्रशिक्षण के घंटों और अकादमिक क्रेडिट की सामग्री की समानता निर्धारित करने के लिए एसएसबी प्रतिष्ठानों में वर्तमान पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगा।

पाठ्यचर्या में वृद्धिः दोनों संस्थान विशिष्ट डिग्री या डिप्लोमा के लिए "अतिरिक्त क्रेडिट" आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री या पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में सहयोग करेंगे।

मानकीकृत मूल्यांकनः आरआरयू कानून द्वारा आवश्यक उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के लिए एक मजबूत मूल्यांकन प्रक्रिया और ग्रेडिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा।

शैक्षणिक संपूर्णता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए, यह साझेदारी मौजूदा और अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री दोनों की आवधिक जांच और सत्यापन को अनिवार्य करती है। इस साझेदारी से यह सुनिश्चित होता है कि पाठ्यक्रम गतिशील बना रहे और उभरते सुरक्षा खतरों के प्रति उत्तरदायी रहे।

इसके अलावा, इसके तहत सशस्त्र सीमा बल अकादमी में एक समर्पित आरआरयू डेस्क की स्थापना की जाएगी। यह प्रशासनिक केंद्र डेटा का प्रबंधन करेगा, दिन-प्रतिदिन के संचार को सुव्यवस्थित करेगा, और मान्यता प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेगा, जिससे विश्वविद्यालय और अर्धसैनिक बल के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित होगा।

यह सहयोग गृह मंत्रालय के "एकीकृत प्रशिक्षण" दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सैद्धांतिक अनुसंधान और व्यावहारिक सीमा प्रबंधन के बीच की खाई को पाटता है। यह समझौता ज्ञापन एसएसबी कर्मियों के कठोर प्रशिक्षण को प्रमाणित करकेउन्हें करियर में प्रगति के अवसर और शैक्षणिक मान्यता प्रदान करता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है।

एक प्रमुख आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय और एक अग्रिम पंक्ति के सीमा सुरक्षा बल के बीच यह तालमेल भारत की सुरक्षा संरचना को पेशेवर बनाने की दिशा में एक कार्यनीतिक कदम है। सामरिक प्रशिक्षण को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ जोड़कर, यह समझौता ज्ञापन यह सुनिश्चित करता है कि एसएसबी अधिकारियों और कर्मियों का समर्पण देश भर में मान्यता प्राप्त औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों में परिलक्षित हो।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

ईरान भी युद्ध से बचने की राह निकालने में उत्सुक नहीं दिख रहा

ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को हमला करके दो बातों को स्पष्ट कर दिया है— पहला यह कि सत्ता परिवर्तन तक वह ईरान पर गोले बरसाता रहेगा और दूसरा यह कि वह न्यूक्लियर के मामले में ईंरान को किसी भी तरह की छूट देने वाला नहीं है।

दरअसल ईंरान ने जिस तरह खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागकर उन सभी को एकजुट किया है।

दरअसल अमेरिका और इजारयल चाहते हैं कि यह युद्ध लम्बा चले।

इसलिए ये दोनों ही चाहते हैं कि ईंरान के सैन्य प्रातिष्ठानों और न्यूक्लियर पैसिलिटी को तबाह करके ईंरान को घुटनों पर लाया जाए। ईंरान तो ध्यान भटकाने के लिए खाड़ी देशों को निशाना बना ही रहा है। लेकिन यह हथवंडा भी ईंरान का उलटा ही पड़ता दिख रहा है। ईंरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर को एक साथ निशाना बनाकर तीनों को अपना दुश्मन बना लिया और खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी ईंरान के न्यूक्लियर पैसिलिटी को तबाह कर दे। ईंरान को इस बात की गलतफहमी थी कि चीन और रूस उसके साथ खड़े होंगे किन्तु इन दोनों ने ठेंगा दिखा दिया। असल में रूस के साथ ईंरान का एक समझौता हुआ है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि यदि ईंरान पर कोई हमला हुआ तो रूस उसकी रक्षा के लिए एस-400 देगा। लेकिन जब इजरायल और अमेरिका ने ईंरान पर हमला किया तो तेहरान में बैठे ईंरानी हुक्मरानों ने रूस से एस- 400 की मांग की। लेकिन रूस ने टका सा जवाब देते हुए पूछा कि अभी जो हमला हुआ है वह तो आतंकी ठिकानों पर हुआ है, ईंरान पर हमले हुए ही कहां है। हक्का-बक्का ईंरान बोले भले ही नहीं किन्तु उसे अब इस बात का एहसास हो गया कि उसकी मदद करके चीन और रूस खाड़ी के देशों को नाराज नहीं कर सकते। आज तो स्थिति यह कर दी है तेहरान ने कि खाड़ी देश खुलकर अमेरिकी और इजरायली हमलों का समर्थन कर रहे हैं। रूस और चीन दोनों ही खाड़ी देशों को नाराज करने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि ईंरान के लिए भला रूस और चीन अमेरिका एवं इजरायल से भी नाराजगी क्यों लें? रही बात भारत की तो भारत जहां इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, वहीं वह किसी भी पक्ष की तरफ खड़ा नहीं दिखना चाहता। भारत अपने भले-बुरे के बारे में अच्छी तरह जानता है। भारत यह भी जानता है कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। भारत को अपने राष्ट्रीय हित के मुताबिक ही अपनी वूटनीति अपनानी है, भारत कर भी वही रहा है। वूटनीति कब किन कारकों के अधीन हो जाती है। इसका एक ही मापदण्ड है राष्ट्रीय हित और रणनीतिक साझेदारी। भारत को बहुत ही सावधानी से इस बवाल से दूरी बनाए रखने की जरूरत है। ईंरान रणनीतिक सूझबूझ से न तो हमले कर रहा है और न ही यह संकेत दे रहा है कि अब तेहरान की नीति शांति और समझौता चाहती है। इसलिए खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि वह सबसे पहले तो ईंरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करे और फिर मौजूदा शासन को अन्यथा इस क्षेत्र में अशांति और युद्ध का माहौल बना रहेगा। यही कारण है कि अमेरिका ने शनिवार को ही यह बयान भी दिया था कि वह न्यूक्लियर ईंरान से निकाल लेगा। बहरहाल जिस तरह ईंरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध में सव्रियतापूर्ण पहल कर रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि जहां अमेरिका व इजरायल रणनीति बनाकर ईंरान के सैन्य एवं न्यूक्लियर प्रातिष्ठानों को बर्बाद कर रहे हैं वहीं ईंरान बिना स्ट्रैटजिक प्लानिग के ही अपनी मिसाइल के जखीरे को खाली कर रहा है। उसे इस बात का अनुमान ही नहीं है कि वह जो कर रहा है, उसके परिणाम क्या होंगे। यह स्थिति कदाचित इसलिए है कि जिस रणनीतिक सैन्य कौशल और राजनीतिक सत्ता के समझ की जरूरत है, वह ईंरान में नहीं रही। बदहवासी से नहीं बल्कि युद्ध जीतने के लिए धैर्य एवं रणनीतिक समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है किन्तु दुर्भाग्य से ईंरान धैर्य का परिचय नहीं दे रहा है और इजरायल तथा अमेरिका चाहते हैं कि उनको लक्ष्य जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए।

आईआईटी बॉम्बे में 'भारत इनोवेट्स डीप-टेक प्री-समिट' का उद्घाटन किया गया

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने दो दिवसीय राष्ट्रीय डीप-टेक शोकेस का उद्घाटन किया; 3,000 से अधिक आवेदनों में से चयनित 137 स्टार्टअप्स मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे

भारत के सर्वश्रेष्ठ डीप-टेक स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार किया जा रहा है

(जीएनएस)।

भारत के सबसे आशाजनक डीप-टेक उद्यमों के राष्ट्रीय प्रदर्शन के रूप में आयोजित होने वाले 'भारत इनोवेट्स डीप-टेक प्री-समिट' का उद्घाटन आज मुंबई स्थित आईआईटी बॉम्बे परिसर के एस्पायर झ्र आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क फाउंडेशन में किया गया।

दो दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के अध्यक्ष प्रो. अजय कुमार सूद ने भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

इस विशिष्ट कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर, आईआईटी बॉम्बे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन तथा आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

यह प्री-समिट भारत इनोवेट्स 2026 यात्रा का प्रारंभिक चरण है, जिसका समापन जून 2026 में फ्रांस के नीस शहर में भारत के वैश्विक नवाचार प्रस्तुतीकरण के साथ होगा। यह कार्यक्रम भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का हिस्सा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि प्रो. अजय कुमार सूद ने भारत की तकनीकी नेतृत्व क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डीप-टेक नवाचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकों को आगे बढ़ाने में शैक्षणिक संस्थानों, शोध तंत्र और स्टार्टअप्स की भूमिका को रेखांकित किया।

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत इनोवेट्स 2026 एक 'पूरे सरकार का प्रयास' है। यह दुनिया के सामने भारत की अत्याधुनिक डीप-टेक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा मंत्रालय को एक साझा मंच पर लाता है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल वैश्विक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने का भी प्रयास है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा के अंक नहीं, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देना है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। उन्होंने निवेशकों और कॉरपोरेट्स से महानगरों से परे होनहार स्टार्टअप्स की पहचान करने का आ'ान किया।

आईआईटी बॉम्बे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन ने नवाचारकताओं और स्टार्टअप संस्थापकों से राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ काम करने का आ'ान किया और कहा कि वे भारत के नवाचार इतिहास का नया अध्याय लिख सकते हैं। उन्होंने नवाचारकताओं को भारत का राजदूत बताया और देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर ने भारत के नवाचार परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां लगभग 2 लाख स्टार्टअप और करीब 125 यूनिकॉर्न हैं कंपनिया। उन्होंने बताया कि 2017झ18 में यह संख्या केवल 24 यूनिकॉर्न थी। वर्तमान में भारत में 1,000 से अधिक निवेशक सक्रिय हैं और हाल के वर्षों में लगभग 70झ80 अरब रुपये का वेंचर कैपिटल भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया गया है।

उन्होंने डीप-टेक वित्तपोषण में कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि कुल वेंचर कैपिटल निवेश में से केवल 4झ5 अरब डॉलर ही डीप-टेक क्षेत्र में गया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष को मंजूरी दी, जो निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास और स्टार्टअप्स को इक्विटी भागीदारी और दीर्घकालिक वित्तपोषण के माध्यम से समर्थन देगा। इस फंड के प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और बीआईआरएसी (डीबीटी) को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही वैकल्पिक निवेश कोष और आईआईटी अनुसंधान पार्कों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। डीएसटी वर्तमान में साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और निधि सीड सपोर्ट योजनाओं के माध्यम से भारत के अनुमानित 8,000-10,000 डीप-टेक स्टार्टअप में से लगभग 30-40% का पोषण कर रहा है।

आईआईटी और आईआईएससी के पारिस्थितिकी तंत्र की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर करंदीकर ने कहा, "डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने में आईआईटी और आईआईएससी की बड़ी भूमिका है।"

आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे ने स्वागत भाषण में कहा कि भारत इनोवेट्स केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक डीप-टेक इकोसिस्टम है, जो तीन स्तंभों-शिक्षा प्रणाली, रणनीतिक निवेशक और कॉर्पोरेट सेक्टर पर आधारित है, जो तकनीक को वास्तविक प्रभाव में बदलने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि देशभर से 3,000 से अधिक स्टार्टअप आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कड़े बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद 13 थीमैटिक क्षेत्रों में 137 सर्वश्रेष्ठ डीप-टेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया।

उद्घाटन के बाद गणमान्य लोगों ने स्टार्टअप प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां उन्होंने स्टार्टअप संस्थापकों से बातचीत की और उनके नवाचारों का मुआयना किया। 70 से अधिक स्टार्टअप्स ने विभिन्न पिच सत्रों में अपने विचार रखे, जिसके बाद निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने रिवर्स पिच के माध्यम से निवेश के प्राथमिक क्षेत्रों और उद्योग की तकनीकी आवश्यकताओं पर चर्चा की। इसमें प्राथमिकता वाले निवेश क्षेत्रों और उद्योग-प्रेरित तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

भारत इनोवेट्स 2026 डीप-टेक प्री-समिट भारत के नवाचार इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाता है और उभरते स्टार्टअप्स को निवेशकों, उद्योग जगत और नीति-निमार्ताओं से जुड़ने का राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम में 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों-एडवांस्ड कंप्यूटिंग, हेल्थकेयर एवं मेडटेक, स्पेस एवं डिफेंस, एनर्जी एवं सस्टेनेबिलिटी, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज एवं मोबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, नेक्स्ट-जेन कम्युनिकेशन, एग्री एवं फूड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्री 4.0 तथा आपदा प्रबंधन में नवाचार प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

भारत इनोवेट्स के बारे में:

भारत इनोवेट्स 2026, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय के रणनीतिक मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में विकसित अनुसंधान आधारित तकनीकी नवाचारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है।

यह कार्यक्रम 22 मार्च 2026 को भी जारी रहेगा, जिसमें अतिरिक्त स्टार्टअप पिच सत्र, नीति चर्चा, निवेशक सहभागिता और ग्रैंड फिनाले एवं पुरस्कार समारोह आयोजित होगा, जहां सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप प्रस्तुतियों को सम्मानित किया जाएगा।

'एक स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को सुदृढ़ बनाना: पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने मॉक ड्रिल में पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया'

(जीएनएस)।

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने एक स्वास्थ्य पर चौथी वैज्ञानिक संचालन समिति की सिफारिशों के अनुरूप, 20 मार्च 2026 को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में "मॉक ड्रिल के दौरान पहचानी गई कमियों को दूर करना" विषय पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया।

राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत तैयारियों को सुदृढ़ करने के प्रयासों के तहत, परिचालन तत्परता, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, प्रयोगशाला प्रतिक्रिया प्रणालियों, जैव सुरक्षा और जैव संरक्षण प्रथाओं और आपातकालीन संचार प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने के लिए दो राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल - "विषाणु युद्ध अभ्यास" (अगस्त 2024) और "वायरल संक्रमण अभ्यास" (नवंबर 2025) - आयोजित किए गए।

कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य इन मॉक ड्रिल से प्राप्त प्रमुख सबक के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जागरुक करना और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए एक संरचित और समयबद्ध दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना था जिससे एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के तहत भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया ढांचे को और मजबूत किया जा सके।

इस कार्यशाला में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन सत्र में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के सचिव श्री नरेश पाल गंगवार; डीएएचडी के पशुपालन आयुक्त डॉ. नवीन बी. महेश्वरप्पा; डीएएचडी के अपर सचिव (पशुधन स्वास्थ्य) श्री राम शंकर सिन्हा, डीएएचडी के संयुक्त सचिव डॉ. मुथुकुमारसामी बी.; और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) रंजन दास शामिल थे।

अपने संबोधन में प्रोफेसर सूद ने कहा कि मनुष्यों में उभरने वाली लगभग 60-70 प्रतिशत संक्रामक बीमारियाँ पशुओं से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण विज्ञान और डेटा-आधारित नीति निर्माण को एकीकृत करने वाले एक समन्वित ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की सिफारिशों से उत्पन्न राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन, उभरते स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए समन्वित और अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि महामारी की तैयारी के लिए कई मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को शामिल करते हुए एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कार्यशाला की चर्चाएँ भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने सभी स्तरों पर जागरूकता, लक्षित क्षमता विकास और प्रभावी संचार रणनीतियों के महत्व पर जोर देते हुए, प्रकोप प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण मानवीय पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की जिनमें मॉक ड्रिल और तैयारी आकलन को संस्थागत बनाना; बीएसएल-3 पारिस्थितिकी तंत्र सहित एकीकृत निगरानी और प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत करना; केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ाना; शासन ढांचे में सुधार करना; निरंतर क्षमता विकास में निवेश करना; और पूवार्नुमान तथा प्रतिक्रियात्मक प्रणालियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। प्रो. सूद ने डीएएचडी के प्रयासों की सराहना की और दोहराया कि मॉक ड्रिल समन्वय और परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण तनाव परीक्षण के रूप में कार्य करती हैं और कहा, "शांति के समय जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा।"

डीएएचडी के सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने महत्वपूर्ण तैयारियों की कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मॉक ड्रिल के महत्व पर जोर दिया। कोविड-19 और बार-बार होने वाले इन्फ्लूएंजा प्रकोपों से मिले सबक का हवाला देते हुए, उन्होंने निगरानी प्रणालियों, प्रयोगशाला नेटवर्क और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने में सिमुलेशन अभ्यासों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और भविष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना है।

इस कार्यशाला में प्रमुख मंत्रालयों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, आईसीएमआर, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान, एनसीडीसी, आईसीएआर, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, डीएएचडी, एनएससीएस, एनडीएमए, बीएसएल 3 नेटवर्क, एक स्वास्थ्य के राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पशुपालन विभाग, आईडीएसपी के तहत राज्य निगरानी अधिकारी और साथ ही पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्र शामिल थे।

इस कार्यशाला में रोग प्रकोप प्रतिक्रिया पर एक टेबल टॉप अभ्यास - "संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास (एसपीए)" - और "एक्स किटाणु संक्रमण - वैश्विक सुरक्षा: स्वाध्याय से अभ्यास तक (केएस-वीएस-सैट)" शीर्षक से एक सिमुलेशन अभ्यास शामिल था। उसका समन्वय भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने किया।

कार्यशाला का समापन सभी प्रमुख हितधारकों की ओर से पहचानी गई कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने और एक स्वास्थ्य ढांचे के तहत भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया संरचना को और सुदृढ़ करने की मजबूत सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर बैठक की अध्यक्षता की

भागीरथी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए हितधारकों का समन्वय आवश्यक है: श्री भूपेंद्र यादव

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज उत्तराखँड के देहरादून में भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (बीईएसजेड) पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की।

बैठक में विचार-विमर्श बीईएसजेड अधिसूचना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर केंद्रीत था। चचार्ओं में संतुलित एवं सतत विकास दृष्टिकोण के माध्यम से पारिस्थितिक प्राथमिकताओं को स्थानीय आकांक्षाओं एवं आजीविका के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

केंद्रीय मंत्री ने गंगा नदी के उद्गम

स्थल भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक संरचित एवं समन्वित संरचना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित अध्ययनों, एकीकृत विकास योजना, स्पष्ट रूप से परिभाषित संस्थागत तंत्रों और सुदृढ़ निगरानी एवं प्रवर्तन प्रणालियों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अवैज्ञानिक विकास अक्सर ऐसी आपदाओं का कारण बनता है जिन्हें टाला जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने जोखिम कम करने के लिए सतर्क एवं सूचित दृष्टिकोण अपनाने का आ'ान किया।

श्री यादव ने हितधारकों के बीच समन्वय के महत्व पर भी प्रकाश डाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण संरक्षण उपायों को विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ सुचारू रूप से संरेखित किया जा सके, जिससे भागीरथी क्षेत्र में पारिस्थितिक अखंडता एवं सामुदायिक कल्याण दोनों की रक्षा हो सके।

इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, निगरानी समिति के सदस्य, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

तेलंगाना में 'छह गारंटी' पर घमासान, केटीआर ने कांग्रेस सरकार से पूछा- आखिर कहां गई वादों वाली फाइल?

(जीएनएस)। तेलंगाना की राजनीति में 'छह गारंटी' को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष K. T. Rama Rao ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Rahul GaQdhi ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से स्पष्ट वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में छह गारंटी को कानून का रूप दिया जाएगा।

KTR ने कांग्रेस को याद दिलाए ये अधूरे चुनावी वादे

KTR ने कहा कि यही छह गारंटी कांग्रेस की चुनावी जीत का आधार थीं। उनके अनुसार किसानों को साल में दो फसलों के लिए 15,000 रुपये की सहायता, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद और छात्रों को 5 लाख रुपये तक का 'विद्या भरोसा कार्ड' देने का वादा किया गया था।

ढाई साल बाद भी नहीं बन पाया कानून

केटीआर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से फाइल पर हस्ताक्षर करने की बात कही थी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी बिल विधानसभा में लाने की घोषणा की गई थी। लेकिन ढाई साल बीत

जाने के बाद भी यह कानून नहीं बन पाया है।

आखिर कहां गई वादों वाली फाइल?

KTR ने तंज कसते हुए कहा कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर वह फाइल कहां गई। उन्होंने कहा कि सरकार को आसान बनाने के लिए इफ्र अब वही प्रावधान शामिल करते हुए एक प्राइवेट मेंबर बिल अगले सप्ताह विधानसभा में पेश करेगी, ताकि छह गारंटी को वैधानिक दर्जा दिया जा सके।

क्या हैं कांग्रेस को होगा नुकसान?

विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी राजनीतिक समीकरणों और जनता के बीच वादों की विश्वसनीयता को लेकर यह मुद्दा तेलंगाना की राजनीति में बड़ा चुनावी विषय बन सकता है। कांग्रेस सरकार की ओर से इस बयान पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सरकार ने बजट 2025-26 के अनुरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निमार्ताओं और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन किया

संशोधनों से कवरेज बढ़ेगा, अनुपालन का बोझ कम होगा और निर्यातक एमएसएमई को लक्षित प्रोत्साहन मिलेगा

संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक के ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं

(जीएनएस)।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) जनवरी 2025 में शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए स्वीकृत ₹100 करोड़ तक की ऋण सुविधा के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ संशोधन किए गए हैं।

मौजूदा 'एमसीजीएस-एमएसएमई' योजना में संशोधन:

अग्रिम अंशदान: 5% अग्रिम अंशदान वापसी योग्य है, चौथे वर्ष से आगे प्रत्येक वर्ष 1% वापसी योग्य है, बशर्ते ऋण खाते का प्रदर्शन संतोषजनक हो।

पात्रता: सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी इस योजना में शामिल किए गए हैं।

मशीनरी/उपकरणों के लिए न्यूनतम परियोजना लागत: उपकरणों/मशीनरी की लागत परियोजना लागत के 60% तक कम कर दी गई है (पहले यह 75% थी)।

गारंटी की अवधि: गारंटी 10 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी।

निर्यातकों के लिए योजना में विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं:

पात्र निर्यातक: लाभ कमाने वाली इकाइयाँ जिन्होंने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में अपने बिक्री कारोबार का कम से कम 25% निर्यात किया हो और कुछ निर्यात प्राप्ति शर्तों को पूरा करती हों। गारंटीकृत ऋण राशि: 20 करोड़ रुपये। अग्रिम योगदान: ऋण राशि का 2% (अधिकतम 40 लाख रुपये); गारंटी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में 1 % की वापसी। गारंटी कवरेज: डिफॉल्ट राशि का 75%। गारंटी शुल्क: पहले वर्ष: शून्य; उसके बाद, प्रत्येक वर्ष: बकाया ऋण का 0.50%। संशोधित योजना का विवरण एनसीजीटीसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रमुख प्रभाव भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का योगदान लगभग 30% और निर्यात में 45% से अधिक है, साथ ही इससे 35 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है। "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ एमएसएमई की आवश्यकता है। एमसीजीएस-एमएसएमई योजना में किए गए संशोधनों से एमएसएमई, जिनमें निर्यातक एमएसएमई भी शामिल हैं, उनको संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि होने की उम्मीद है जिससे भारत के विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

अलविदा जुम्मा पर चाक-चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था, थाना करेली पुलिस रही पूरी तरह मुस्तैद

प्रयागराज

आज अलविदा जुम्मा के दृष्टिगत थाना करेली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ एवं चाक-चौबंद रही। थाना अध्यक्ष आशीष सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी।

नमाज के दौरान क्षेत्र की सभी मस्जिदों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रही। थाना अध्यक्ष द्वारा स्वयं घुड़सवार पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उन्होंने विभिन्न मस्जिदों पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

पुलिस की सक्रियता एवं सतर्कता के चलते नमाज शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न हुई। क्षेत्र में कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

हादसे में गौभक्त फरसा वाले बाबा की हुई दर्दनाक मौत : बाबा की हत्या किए जाने की अफवाह से हुआ बवाल

-अफवाह के बाद ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

-पुलिस पर किया पथराव, लाठीचार्ज करके पुलिस ने यातायात कराया सुचारू

-डीएम और एसएसपी ने कहा हादसे में हुई मौत

-ग्रामीणों का आरोप गौ-तस्करों ने बाबा को कुचला

-डीएम ने दिए जांच के आदेश

मथुरा (जीएनएस)। ब्रज के प्रसिद्ध गौ-रक्षक, गौभक्त सन्त चंद्रशेखर (फरसा वाले बाबा) की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके बाद शनिवार सुबह छाता और कोसीकलां क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना के बारे में प्रशासन ने घने कोहरे में सड़क हादसा होना बताया है तो वहीं दूसरी ओर फरसा वाले बाबा के समर्थक इसे हत्या बता रहे हैं। इस कारण पूरे क्षेत्र में अशांति के साथ हाईवे पर बवाल हो गया। दूसरी ओर डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के करीब 4 बजे पुलिस चौकी कोटवन के नवीपुर के पास एक ट्रक में गौ-वंश तस्करी की सूचना मिलने पर फरसा वाले बाबा अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए और नागालैंड नंबर के एक कंटेनर को रोककर जांच कर रहे थे। बताते हैं कि कंटेनर में साबुन, फिनाइल और शैम्पू भरे हुए थे। उसी दौरान अचानक आए कोहरे के कारण पीछे से आ रहे

राजस्थान नंबर के ट्रक ने कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे फरसा वाले बाबा की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई और ट्रक चालक घायल हो गया। दूसरी ओर कुछ ग्रामीणों और बाबा के अनुयायियों का आरोप है कि बाबा, बाइक से गौ-तस्करों का पीछा कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें जानबूझकर कुचला गया है। कोटवन चौकी क्षेत्र में नवीपुर के पास हुई इस घटना के बाद लोगों ने एक युवक को मौके से पकड़ लिया, जबकि तीन लोग लोग भाग गए। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर फरसा वाले बाबा की गौ-तस्करों द्वारा ट्रक से कुचल कर हत्या किए जाने की अफवाह फैलने के बाद थाना छाता क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थकों ने बाबा का शव रखकर जाम लगा दिया। इसके बाद स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए जाम में फंसे वाहनों तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। घटना की सूचना मिलते ही आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश पांडेय मौके पर पहुंच गए, इसके बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आयी और डीआईजी के सामने भी पथराव होने पर पुलिस ने सख्ती करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। उधर डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि फिर भी मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी। उनका कहना है कि लोगों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करायी जाएगी। एसएसपी श्लोक कुमार ने क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया था।

संज्ञान : जांच के बाद सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

मथुरा (जीएनएस)। थाना कोसीकलां क्षेत्र स्थित नवीपुर के पास गौभक्त संत चन्द्रशेखर (फरसा वाले बाबा) की मृत्यु होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए बवाल के बाद इसकी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिराकियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक संत चंद्रशेखर (फरसा वाले बाबा) के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जैंत करके पुलिस-प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जांच करके घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि अपराधी किसी हालत में बख्शे न जाएं। वहीं पुलिस-प्रशासन को सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मामले की गहनता से और निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे की सच्चाई सभी के सामने आ सके। बता दें कि थाना कोसीकलां क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। हालात नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। संभावना है कि जल्द ही जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

नमाजियों को गुलाब का फूल देकर व माला पहनकर किसान यूनियन ने किया स्वागत, पुलिस सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा हुई

(जीएनएस)।

फतेहपुर। ऐरायां विकास खंड के मोहम्मदपुर गौंती, सुल्तानपुर घोष, उमरपुर गौंती, आरामपुर बसई, अल्लीपुर बहेरा, प्रेमनगर, अफोई सहित अन्य गांवों के मस्जिदों तथा दरगाहों में पुलिस सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा हुई।

मैनपुरी घाट (मंडवा) ईदगाह में न सुबह साढ़े आठ बजे हाफिज हसन के नमाज अदा कराई गई। यहां पर मंडवा, कटरा, सलेमपुर, सेनीपुर सहित अन्य गांव के लोग हजारों की संख्या में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। नमाज अदा होने के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट टीम की ओर से गुलाब के फूल देकर तथा माला पहनाकर नमाजियों का स्वागत किये और गले मिलकर ईद की बधाई दी। यूनियन के पदाधिकारी बालराज सिंह ने बताया कि यह कार्य कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इससे आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षक श्यामसुंदरलाल श्रीवास्तव, एसआई सुरेश कनौजिया और संजीव कटारिया भोर पहर से ईदगाह पर डटे रहे। इस कार्यक्रम में यूनियन से मुन्ना सिंह, राकेश कुमार चौरसिया, मुकेश सिंह, विनोद सिंह शामिल रहे।

जम्मू-कश्मीर में डिगडोल-पंथ्याल ट्विन ट्यूब टनल किस तरह जिंदगियां बदलने वाली हैं

(जीएनएस)।

दशकों तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रामबन, डिगडोल और पंथ्याल के बीच के क्षेत्र को एक ऐसे नाम से जाना जाता था जिसके बारे में स्थानीय लोग चिंता किए बिना शायद ही कभी बात करते थे - खूनी नाला। चट्टानें गिरने, भूस्खलन, भारी बारिश और बड़ी संख्या में जानलेवा दुर्घटनाओं के कारण अक्सर यातायात ठप हो जाता था। यात्री अक्सर घंटों, कभी-कभी तो दिनों तक, सड़क साफ होने का इंतजार करते हुए फंसे रहते थे।

आज राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रामबन-बनिहाल खंड में डिगडोल से पंथ्याल तक चार लेन वाली ट्विन ट्यूब सुरंगों के निर्माण के साथ यह कहानी बदल रही है।

दिगडोल निवासी रतन को याद है कि पहले यात्रा कितनी अनिश्चित हुआ करती थी। वे कहते हैं की 'पहले जब चट्टानें गिरती थीं और तेज बारिश होती थी, तो कई लोगों को दोनों तरफ कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। अब हम दिगडोल से रामसू-मगरकोट की तरफ सिर्फ 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। सुरंग निर्माण के लिए मैं सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।'

एनएच-44 के रामबन-बनिहाल खंड के चल रहे चार लेन निर्माण कार्य

के अंतर्गत, डिगडोल-पंथ्याल ट्विन ट्यूब टनल इस चुनौतीपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित रामबन-बनिहाल खंड कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

अपनी खड़ी ढलान और लगातार भूस्खलन के लिए जाना जाने वाला यह खंड लंबे समय से यात्रियों और परिवहनकर्ताओं दोनों के लिए चुनौतियां पेश करता रहा है। इस महत्वपूर्ण मार्ग को सुरक्षित, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख अवसंरचना पहल - डिगडोल-पंथ्याल ट्विन ट्यूब टनल परियोजना - पूर्ण होने के करीब है।

नाबालिक के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी का आरोप

(जीएनएस)।

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी मां ने नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी अश्लील हरकत करने का गांव के लड़के ऊपर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है।

गांव निवासिनी महिला ने शुक्रवार को थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री है। गांव का ही एक लड़का करीब दो माह से उसके मोबाइल पर बातचीत करता रहा। 19 मार्च रात को सभी लोग घर पर पर सोये हुए थे। रात्रि करीब 11 बजे जब नींद खुली तो पुत्री को गायब देखा तो पति को जगाया और पुत्री की खोजबीन करने लगे। खोजबीन के दौरान पुत्री को गांव के शिवबाबू के साथ घर के बगल स्थित खंडहर में देखा गया। मां का आरोप हैकि इस दौरान आरोपी युवक उसके पुत्री के कपड़े उतारकर नाजुक अंगों के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें कर रहा था। उसे पकड़ने की जब कोशिश की गई तो वह धक्का देकर पुत्री तथा परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। महिला ने बताया कि उक्त युवक दबंग व गुंडा किस्म का व्यक्ति है। महिला ने मुकदमा लिखकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रभु गिरिराज की शरण में पहुंची राष्ट्रपति : परिक्रमा करते हुए डूबी रहीं भक्ति में

-दानघाटी मंदिर में दूध चढ़ाकर की पूजा-अर्चना

-राष्ट्रपति पर होती रही फूलों की वर्षा, बच्चों ने संस्कृत गीतों के मध्य किया स्वागत

मथुरा (जीएनएस)। श्रीकृष्ण की नगरी में आध्यात्मिक यात्रा पर आयीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पूरी तरहा भक्ती में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे दिन वह गोवर्धन पहुंची, वहां उन्होंने प्रभु गिरिराज जी महाराज की 21 किमी. परिक्रमा की शुरूआत नंगे पांव करते हुए श्रद्धा, आस्था एवं सादगी का संदेश दिया। परिक्रमा के दौरान वह कुछ दूरी तक नंगे पैर चलीं, इसे देखकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह का संचार हो गया। परिक्रमा शुरू करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दानघाटी मंदिर पहुंचकर प्रभु गिरिराज जी की पूजा-अर्चना करते हुए प्रभु पर दूध चढ़ाया। इस बीच वहां का वातावरण गिरिराज महाराज की जय के जयघोष से गुंजायमान हो गया। इस बीच राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के साथ उनके

परिजन भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति, गोल्फ कार्ट में परिक्रमा मार्ग में चलीं तो आगरा मंडल के कमिश्नर नगेंद्र प्रताप सिंह उनके साथ रहे। वहीं दूसरी गोल्फ कार्ट में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और गोवर्धन विधायक मेघश्याम सिंह पीछे चलते रहे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गोवर्धन और राधाकुंड को प्रशासन ने दुल्हन की तरह सजाया है। प्रशासन ने जगह-जगह भव्य तोरण द्वार बनाए थे, वहीं स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा कर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने भी दोनों हाथ जोड़कर तथा हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मौजूद स्थानीय लोग और श्रद्धालु काफी उत्साहित हो गए। इस दौरान राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने पारंपरिक परिधान में उनका स्वागत किया। वहीं संस्कृत विद्यालयों के छात्रों ने मंत्रोच्चार एवं स्वागत गीतों के साथ माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। इससे पूर्व पूरे परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन और राधाकुंड कस्बा में विशेष साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को देखकर श्रद्धालु और स्थानीय लोग काफी खुश दिखाई दिए। डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह ने मौके पर रहकर खुद व्यवस्थाओं को संभाला और हर व्यवस्था को गंभीरता से मॉनिटर किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विगत 19 मार्च की शाम को तीन दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर श्रीकृष्ण की नगरी पहुंची थीं। गोवर्धन में प्रभु दर्शन, पूजा-अर्चना और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद वह विगत (शनिवार) शाम को नई दिल्ली रवाना हो गईं। श्रीकृष्ण की नगरी में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू की आध्यात्मिक यात्रा ने जहां प्रशासनिक तैयारियां बेहतर रहीं तो वहीं राष्ट्रपति को देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह के साथ भक्ति का संगम भी देखने लायक रहा।

मथुरा में गौभक्त बाबा की मौत का मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान : जांच के बाद सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

मथुरा (जीएनएस)। थाना कोसीकलां क्षेत्र स्थित नवीपुर के पास गौभक्त संत चन्द्रशेखर (फरसा वाले बाबा) की मृत्यु होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए बवाल के बाद इसकी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिराकियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक संत चंद्रशेखर (फरसा वाले बाबा) के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जैंत करके पुलिस-प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जांच करके घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि अपराधी किसी हालत में बख्शे न जाएं। वहीं पुलिस-प्रशासन को सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मामले की गहनता से और निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे की सच्चाई सभी के सामने आ सके। बता दें कि थाना कोसीकलां क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। हालात नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। संभावना है कि जल्द ही जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हुए बवाल में विहिप के प्रांतीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष हुए घायल

मथुरा (जीएनएस)। थाना कोसीकलां क्षेत्र स्थित नवीपुर के पास चव्द्रशेखर (फरसा वाले बाबा) मौत के बाद बिगड़े हालात में विहिप के दो पदाधिकारी भी पथराव में घायल हो गए। फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हुए बवाल के बीच आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश पांडेय ने घटनास्थल पर बवाल को शांत करने के लिए वार्ता के लिए संभ्रान्त लोग बुलाए थे। उसी दौरान वार्ता के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। अचानक हुए पथराव में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के दो पदाधिकारी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार विहिप के प्रांतीय अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल (स्वीटी सुपारी) और जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह को डीआईजी ने घटनास्थल पर स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए वार्ता करने के लिए बुलाया था। उसी बीच वार्ता के दौरान ही भीड़ आक्रोशित हो गई और अचानक पथराव शुरू कर दिया। पथराव में विहिप के दोनों पदाधिकारी घायल हो गए। पथराव होते ही मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और आनन-फानन में विहिप के घायल पदाधिकारियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शी लोगों के मुताबिक पथराव एक सासाथ काफी तेज किया था, जिससे आसपास खड़े कई अन्य लोग भी चुटैल हो गए। इसके बाद डीआईजी ने सख्त रूख अपनाया तो पथराव करने वाले असामाजिक तत्व भाग खड़े हुए।

पुलिस ने गांजा बेच रहे एक तस्कर को किया गिरफ्तार

मथुरा (जीएनएस)। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित मोती मंजिल के पास से पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी कृष्णानगर विपिन तोमर और एसआई नितिन तेवतिया पुलिस टीम के साथ मादक पदार्थ तस्करों की तलाश में जुटे हुए थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर

से सूचना मिली की हाईवे प्लाजा के पास मोति मंजिल के सामने एक मादक पदार्थ तस्कर गांजा बेच रहा है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी कृष्णानगर विपिन तोमर और एसआई नितिन तेवतिया पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखते ही गांजा बेच रहा तस्कर भागने लगा। पुलिस ने भागने का प्रयास कर रहे मादक पदार्थ तस्कर सद्दाम पुत्र यामीन उर्फ यासीन निवासी किराए का मकान ज्योतिनगर मदीना मस्जिद के पीछे थाना कोतवाली को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 6 सौ 70 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय भेज दिया है।

भारत विद्युत शिखर सम्मेलन में भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक का आयोजन किया गया

नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण और लचीलापन तथा संस्थागत क्षमता भारत-अफ्रीका सहयोग के क्षेत्र हैं: श्री मनोहर लाल

(जीएनएस)।

भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन (21.3.2026) नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने की।

बैठक में विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, मलावी सरकार के ऊर्जा एवं खनन मंत्री डॉ. जीन मथांगा, अफ्रीका50 के सीईओ एलेन एबोबिस,

कई अफ्रीकी देशों के मंत्री, अफ्रीकी संघ और अफ्रीका50 के नेता, राजदूत, उच्चायुक्त, विद्युत कंपनियों के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थान, विकास भागीदार और उद्योग जगत के नेता उपस्थित थे।

इन चचाओं में एक स्पष्ट और दूरदर्शी दृष्टिकोण यह उभर कर आया कि भारत और अफ्रीका ठोस परिणामों पर केंद्रित एक संरचित और कार्य-उन्मुख साझेदारी के माध्यम से अपने सहयोग को और गहरा करेंगे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और अफ्रीका नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, परस्पर जुड़े ग्रिड प्रणालियों के विकास, ऊर्जा भंडारण और लचीले समाधानों को बढ़ावा देने और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इसमें विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत के व्यापक अनुभव और अफ्रीका की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने निवेश-आधारित सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य एक समावेशी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करने में सक्षम हो। श्री मनोहर लाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक विकास को गति देने, गरिमा सुनिश्चित करने और अवसरों को खोलने के लिए बिजली महत्वपूर्ण है। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संपर्क के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग के रूप में 'एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड' की परिकल्पना का भी उल्लेख किया। उन्होंने अफ्रीकी साझेदारों का हार्दिक स्वागत किया और विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा प्राप्त करने की साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका, वैश्विक जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं।

कमरे में फंदे से लटकी मिली किशोरी

(जीएनएस)।

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के कुंवरपुर मजरे कूंधन गांव में शुक्रवार दोपहर को घर के कमरे के अंदर फांसी का फंदा बना किशोरी ने लटककर जान दे दी थी।

गांव निवासी लवकुश पासवान की पुत्री लक्ष्मी (17) मां सुमन की डांट से क्षुब्ध होकर दोपहर करीब 12 बजे घर के अंदर कमरे में जाकर दुपट्टे के सहारे फांसी की फंदे पर लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। बकरी को पीट देने पर उसकी सींग टूट जाने पर घटना की वजह बताई गई थी, जबकि क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रेम प्रसंग होने की चर्चा रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने बताया कि किशोरी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया था।